

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of
Management Sciences[PK]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pinteau,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA

Titus PopPhD, Partium Christian
University, Oradea, Romania

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political
Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yallickar
Director Management Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director, Hyderabad AP India.

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Awadhesh Kumar Shirotiya
Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.)

S. Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

S. KANNAN
Annamalai University, TN

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University



“ भारत में कृषि ऋण व्यवस्था का आर्थिक सर्वेक्षण उमरिया जिले के विशेष सन्दर्भ में ”

डॉ. राजू रैदास¹, कन्हैया कुमार विश्वकर्मा²

¹अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत.

²अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

प्रस्तावना एवं शोध सारांश :-

उमरिया जिला प्राकृतिक दृष्टि से काफी सम्पन्न है, किन्तु प्राकृतिक का पूर्ण निदोहन न होने के कारण यहाँ का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है जैसे की प्रथम अध्याय के अध्ययन से स्पष्ट है। खनिज पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में भण्डार है। उद्योग.धन्धे का विकास हो रहा है, संचार एवं सदेहवाहक की स्थिति संतोषजनक है। यातायात का विकास तीव्र गति से हो रहा है। बैंकिंग की सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्र में अप्रयाप्त है कृषि में तकनीकी परिवर्तन आ रहा है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। विद्युत प्रदाय की मात्रा में कमी है तकनीकी शिक्षा नाममात्र की कही जा सकती है। वनों का समुचित विकास नहीं हो पाया है वनों का क्षेत्रफल पर्याप्त मात्रा में होने पर भी वनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं किस्म दयनीय है यदि उमरिया जिला को सम्पन्न जिला किन्तु निवासी विपन्न कहीं जाए तो अतिशयोक्ति न होगा। आदिवासी बाहुल्य जिला होने के बावजूद भी जिस अनुपात में विकास होना चाहिए उस अनुपात में इस जिले का विकास नहीं हो पा रहा है, जो स्वतंत्र भारत सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ कि ७५प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। अतः देश के विकास के लिए कृषि ऋण व्यवस्था का होना आवश्यक है।

भारतीय कृषि को मानसून का जुँवा कहा जाता है, मानसून मेहरवान होने पर कृषि में अच्छी फसल की उपज प्राप्त की जा सकती है। किन्तु वर्तमान कृषि पद्धति को देखते हुए कृषि ऋण व्यवस्था पर



आधारित हो गयी है। चूँकि महगाई व मानसून की की अनिश्चितता के कारण कृषि विकास संभव नहीं है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मुलतः कृषि पर आधारित है, प्राचीनकाल से ही भारत के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण कृषक ऋणों एवं उनके व्याज का समय पर भुगतान नहीं कर पाते थे। परिणामस्वरूप कृषकों के ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही जाते है। प्राचीन समय में कृषक गरीबी एवं ऋणग्रस्ता के कारण न तो खेती के तरीकों में सुधार कर सकता था और न ही अपनी आर्थिक उन्नति के बारे में विचार कर पाता था क्योंकि उस समय गाँवों में साख की कोई सुविधा नहीं थी। इस लिए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार बार साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। और साहूकारों के व्याज की दर एवं ऋण देने की शर्तें इतनी कठिन होती थी कि गरीब कृषक की आय का बड़ा भाग व्याज एवं ऋण चुकाने में ही चला जाता था। इस कारण कभी भी कृषक ऋण से मुक्ति नहीं हो पाता था। भारतीय कृषकों की इन कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से सहकारी बैंक को एक और कल्याणकारी संस्था माना जाता है।

अतः समय रहते भारतीय कृषि तथा कृषकों को बचाने की उचित व्यवस्था करने की त्वरित आवश्यकता है। अन्यथा हमारे देश में आने वाले समय में कृषि व कृषकों की स्थिति संकटमय हो सकती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऋण व्यवस्था में कृषि शाख ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं एवं योजनाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

कृषि एवं ग्रामीण ऋण व्यवस्था का अर्थ :-

भारतीय कृषकों में कृषि कार्य के लिए जिन आवश्यकताओं की पूर्ति जिस साख या ऋण से की जाती है उसे कृषि ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत माना जाता है।

आज अधिकांस कृषक समुदाय गरीबी में जी रहा है, जबकि कृषि में उत्पादन प्राप्ति के लिए लागत काफी बढ़ गई हैं। इस लागत को पूरा कर पाने की क्षमता उन गरीब कृषकों के पास लगभग नहीं के बराबर है। साथ ही उनके उत्पादकों के लिय बाजार और कीमत इतनी नहीं है कि लागत की वसूली सही समय पर और सही तरीके से कर सकें। इस लिए अनिवार्य बन जाता है कि हम उनकी इन समस्याओं का समाधान करें उसके दो ही तरीके हो सकते है। एक तो हम बैंक से प्रयाप्त ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायें या उत्पादों के बाजार या कीमत ऐसी कर दें कि उन्हें लागत व मुनाफा प्रयाप्त मात्रा में मिल सके।

कृषि विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था :-

प्रायः कृषि विकास से तात्पर्य कृषि उत्पादकता वृद्धि से लिया गया है। परन्तु यांत्रिक क्रांति के बाद आज उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के अपेक्षाकृत कृषि विकास को आर्थिक विस्तृत अर्थों में प्रयोग करते हुए कृषि हेतु नई दशाओं को परिवर्तित अनुकूलन एवं उसकी अन्तर्निहित संभावनाओं को पूर्ण विकास है। कृषि विकास की समस्याएँ मात्र वर्तमान उत्पादन हेतु नई तकनीक लाने की ही नहीं बल्कि इसमें संरचनात्मक आधार में परिवर्तन की भी है। जिसमें

कृषि के संरचनात्मक आधार में परिवर्तन के लिए बैंकिंग संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिक के आधार पर कृषि का विकास करने के उद्देश्य से देश में बड़ी मात्रा में तथा शर्तों पर कृषकों का बैंकिंग संस्थाओं की सुविधा प्रदान की गई है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य :-

भारतीय कृषक ऋण का बोझ कन्धों पर लेकर जन्म लेता है , ऋण में ही जीता है और ऋण में ही मर जाता है।

अतः भारत में विगत पिछले दशकों से कृषि पर कृषकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है, इसके लिए हर वर्ग को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।

किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रगति उस क्षेत्र में उपलब्ध वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करती है। बिना वित्तीय सहायता के कृषि की प्रगति संभव नहीं हो सकती है। हमारे देश में कृषि वित्त के लिए ही सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। सरकार एवं सहकारी क्षेत्र से जुड़े राजनेताओं एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की तस्वीर बदल दिये जाने के दावों समय - समय पर किये जाते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र कार्य का विशेष अध्ययन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :-

१. भारतीय कृषि ऋण के लिए किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।
२. भारतीय कृषि ऋण व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करना।
३. भारतीय कृषि ऋण लोगों को ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का अध्ययन करना।
४. भारतीय कृषि विकास के सन्दर्भ में उमरिया जिले की सहकारी बैंकों की स्थिति का आर्थिक सर्वेक्षण करना।
५. भारतीय सहकारी बैंकों द्वारा सदस्य समितियों की साख संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाओं का अध्ययन करना।
६. भारतीय कृषकों के लिए सहकारी बैंकों द्वारा अपनाई गई ऋण प्रक्रिया एवं ऋण योजनाओं का आर्थिक सर्वेक्षण करना।
७. भारतीय कृषि कार्य के लिए उमरिया जिले के कृषकों को समय पर ऋण प्राप्त होता है या नहीं तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है या नहीं।
८. भारतीय कृषि कार्य के लिए उमरिया जिले के कृषकों को जो ऋण प्रदान किये जाते हैं उससे कृषकों के उद्देश्य पूरा होता है या नहीं।
९. भारतीय कृषि कार्य के लिए उमरिया जिले के कृषकों को जो ऋण प्रदान किये जाते हैं उन ऋणों की अदायगी या वसूली की क्या व्यवस्था है।
१०. भारतीय कृषि कार्य के लिए उमरिया जिले के सहकारी बैंकों एवं हितग्राहियों की विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाईयों का अध्ययन करना एवं उनके समाधान के लिए सुझाव देना।

कृषि एवं ग्रामीण ऋण व्यवस्था :-

भारतीय कृषकों में ऋण एवं साख व्यवस्था बनाने के लिए नार्वाड, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सेट्रल बैंक एवं अन्य बैंकों की स्थापना की गई है। एवं अन्य बैंक जैसे लीड बैंक, स्वसहायता समूह , सूक्ष्म वित्त, किसान क्रेडिट कार्ड नगद अन्तरण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, एवं शासन के द्वारा अन्य कई योजना चलाई जा रही है। जो प्रमुख निम्न लिखित हैं :-

1. नार्वाड योजना :-

नार्वाड का गठन भारतीय कृषकों के लिए कृषि ऋण प्रदान करने प्रमुख संस्था है। इसके अन्तर्गत अनेक वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करती है। जो संस्थाएँ प्रमुख हैं जैसे भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय मध्य ग्रामीण बैंक आदि।

2. सेट्रल मध्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :-

इस बैंक की स्थापना २ अक्टूबर १९७५ को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण में निवासरत पिछड़े लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी बैंकिंग ऋण साख सुविधा प्रदान कराना है।

3. भूमि विकास बैंक :-

भारतीय कृषकों को कृषि कार्य के लिए दीर्घकालीन ऋण की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक को भूमि बन्धक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषकों को भूमि खरीदने, भूमि सुधार, ऋणों के भुगतान आदि के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

4. स्व-सहायता समूह योजना :-

स्व-सहायता समूह योजना की स्थापना ०१/०४/१९६६ को शुरू की गई थी जो भारतीय कृषकों एवं जरूरतमंदों को समान आर्थिक स्थिति वाले गरीबों को स्वैच्छिक एक समूह बनाकर इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रत्येक समूह में कम से कम १५-२५ व्यक्तियों का एक समूह होता है। ये सदस्य अपने बचत एकत्र कर आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करते हैं।

5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना :-

भारतीय कृषकों को कृषि कार्य हेतु अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ १९६८ में किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषकों को सेट-साहूकारों के चुंगल से बचाना है। तथा न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि कार्य हेतु ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह सुविधा भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान की जा सकती है।

6. प्रधानमंत्री जन-धन योजना :-

माननीय स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस योजना का सुभारंभ २८ अगस्त २०१४ को किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत खाते खोलने से लेकर राशि स्थानान्तरण, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, पेशन, बीमा, तथा भारत में निवासरत गरीबों को आर्थिक एवं

सामाजिक सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराना आदि सम्मिलित है।

सुझाव :-

१. उमरिया जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय व्यवस्था (रूपये के लेन-देन) हेतु बैंकिंग संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे भारतीय कृषकों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है उसे ऋण लेने में आसानी हो। किसी प्रकार की कोई कटिनाई न हो।
२. उमरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कृषकों को उत्पादनों का उचित मूल्य दिलाने के लिए तथा उत्पादनोत्तर पर होने वाली अनावश्यक क्षति को रोकने के लिए उमरिया जिले के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में उचित भण्डारण एवं वितरण की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए।
३. उमरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कृषकों को समय - समय पर कृषि वित्त योजनाओं एवं नवीनतम कृषि योजनाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्पन्न कराना चाहिए जिससे कृषि वैज्ञानिकों एवं ऋण के उपयोग के अनुभवों एवं उनके अनुसंधानों को भारतीय कृषकों तक पहुंचाया जा सके।
४. उमरिया जिले में निवासरत कृषकों को समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की संचालित योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार कराना चाहिए जिससे उमरिया जिले में निवासरत ग्रामीण कृषकों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके एवं उसका उचित ढंग से उपयोग किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

१. भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, जी.के.गुप्ता वृन्दा पब्लिकेशन दिल्ली
२. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका जिला सांख्यिकीय कार्यालय उमरिया, जिला उमरिया मध्यप्रदेश।
३. www.google.com/wikipedia.com



डॉ. राजू रैदास
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत.



कन्हैया कुमार विश्वकर्मा
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org